''आने वाला कल समाज के हित के लिए पारम्परिक ऊर्जा के स्थान पर अक्षय ऊर्जा का होगा– अध्यक्ष, विद्युत नियामक आयोग''

जयपुर, 19 जून, 2015

आने वाला कल समाज के हित के लिए पारम्परिक ऊर्जा के स्थान पर अक्षय ऊर्जा का होगा तथा इस परिवर्तन में उपभोक्ता शिक्षा व जागरूकता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उक्त कथन राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष विश्वनाथ हीरामथ द्वारा व्यक्त किये गये। हीरामथ 'कट्स' व जर्मन संस्था एफ.ई.एस., इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से ''ग्रीन ग्रोथ एवं एनर्जी सिक्योरिटी इन इंडिया : पोलिटिकल इकोनोमी ट्रांसफोरमेशन एण्ड चैलेन्जेस'' विषय पर आयोजित एक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे।

हीरामथ ने अपने उद्बोधन में विद्युत सेवा तंत्र के विभिन्न खण्डों में आने वाली चुनौतियों का वर्णन करते हुए कहा कि ये सभी चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन ऐसी नहीं हैं जिनको जीता नहीं जा सकें। जहां तक ढ़ांचागत चुनौतियों का प्रश्न है, इनको तकनीकी सुधारों द्वारा काबू में किया जा सकता है, लेकिन चूंकि विद्युत क्षेत्र आने वाले दिनों में और अधिक जटिल होता जा रहा है इसलिए उपभोक्ता शिक्षा व जागरूकता व उपभोक्ताओं की सक्रिय भूमिका इसमें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हीरामथ ने अपने उद्बोधन में यह घोषणा की कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा अपने हाल ही के टैरिफ आदेश में उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता के लिए 50 लाख रूपये प्रति डिस्कॉम के बजट का प्रावधान किया है तथा इसके लिए उन्होंने 'कट्स' जैसी संस्थाओं को इस क्षेत्र में और अधिक सक्रियता से आगे आकर नियामक आयोग के साथ हाथ बढ़ाने का आग्रह किया है।

प्रारम्भ में 'कट्स' महामंत्री प्रदीप एस महता ने अपने स्वागत उद्बोधन में बताया कि भारत में विद्युत मांग व आपूर्ति के अंतर को कम करना हमेशा से ही एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है जिसको कि कुशल विद्युत उत्पादन तंत्र द्वारा दूर किया जा सकता है जिसमे अक्षय ऊर्जा का अंश अधिक से अधिक हो और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भारत में ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। इन सभी के लिए सरकारों को सख्त से सख्त कदम उठाते हुए महत्वपूर्ण फैसले लेने होंगे। महता ने अपने उद्बोधन में इस बात पर भी जोर दिया कि उक्त फैसले लेते समय विकास और पर्यावरण के मध्य संतुलन की स्थिति भी बनाए रखने की आवश्यकता है। महता ने प्रश्नात्मक वक्तव्य में कहा कि हालांकि सरकारें स्वच्छ ऊर्जा विकास की आवश्यकता व अवसरों को समझती हैं और इसे प्राथमिकता भी देती है लेकिन क्या यह प्रयास देश में ऊर्जा परिवर्तन के लिए सम्पूर्ण है?

जर्मन संस्था फ्रेड्रिश इबर्ट स्टिफ्टंग के भारत प्रतिनिधि मार्क सेक्सर ने अपने उद्बोधन में घोषणा की कि ऊर्जा परिवर्तन पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस पूर्ण हो चुकी है तथा अक्षय ऊर्जा की संभावित भूमिका तेजी से उभर कर आई है। उन्होंने कहा कि चूंकि इस विषय पर बहस पूरी हो चुकी है, इसलिए इसको प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए चर्चाएं जरूरी है। सेक्सर ने कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस आशावाद के समर्थन में तीन मुख्य बदलाव देखने को मिले हैं। प्रथम, पारम्परिक ऊर्जा के मुकाबले स्वच्छ ऊर्जा की कीमतों में गिरावट, द्वितीय घरेलू व औद्योगिक स्तर पर संग्रहण की सुविधा का विकास जिसके द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादन की रूक– रूक कर आने वाली प्रवृत्ति का समाधान किया जा सके तथा ऊर्जा परिवर्तन हेतु राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसमें हाल ही में जी– 7 देशों द्वारा इस दशक के अंत तक कार्बन इकोनोमी को समाप्त करने की शपथ लेना सम्मिलित है।

ऊर्जा सुरक्षा के समक्ष चुनौतियां सर्वविदित है, लेकिन इनके समाधान भी मौजूद है। ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक कारगर रणनीति, इच्छा शक्ति की आवश्यकता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में भारत में भी हरित विकास व ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। तथ्यों, आंकड़ों व तकनीकी सक्षमता महत्वपूर्ण हैं लेकिन पर्याप्त नहीं है। राजनीतिक, आर्थिक तंत्र व प्रक्रिया जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें:
उदय एस. मेहता (मो.: 98292 85926), गौरव शुक्ला (मो.: 99822 22822)